



मंत्रिमण्डल

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और एमटीएनएल में नई जान डालने की योजना और दोनों के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दी

दूरसंचार पीएसई को 4जी स्पैक्ट्रम आवंटित किया जाएगा

20,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डालने के माध्यम से वित्त पोषण

15,000 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक बॉन्ड के लिए सॉब्रन गारंटी

आकर्षक वीआरएस की लागत केन्द्र सरकार वहन करेगी

प्रविष्टि तिथि: 23 OCT 2019 4:58PM by PIB Delhi

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 4जी सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन, सॉब्रन गारंटी सहित बॉन्ड्स जारी करने के माध्यम से ऋण अदायगी की नई रूपरेखा बनाने, कर्मचारी लागत में कमी और परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से बीएसएनएल एवं एमटीएनएल में नई जान डालने तथा बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित को मंजूरी प्रदान की गई:-

1. बीएसएनएल और एमटीएनएल को 4जी सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन, ताकि ये पीएसयू ब्रॉडबैंड और अन्य डाटा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सकें। उक्त स्पैक्ट्रम का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा इन पीएसयू में 20,140 करोड़ रुपये मूल्य की पूंजी डालकर किया जाएगा, इसके अलावा इस स्पैक्ट्रम मूल्य के लिए जीएसटी के तौर पर 3,674 करोड़ रुपये की राशि का वहन भी भारत सरकार द्वारा बजटीय संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा। इस स्पैक्ट्रम आवंटन का उपयोग करते हुए, बीएसएनएल और एमटीएनएल 4जी सेवाएं उपलब्ध कराने, बाजार में प्रतिस्पर्धा करने तथा अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में हाई स्पीड डाटा उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकेंगे।
2. बीएसएनएल और एमटीएनएल 15,000 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक बॉन्ड्स भी जारी करेंगे, जिसके लिए सॉब्रन गारंटी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त संसाधनों के साथ बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने मौजूदा कर्ज की अदायगी की नए सिरे से रूपरेखा तैयार करेंगे तथा सीएपीईएक्स, ओपीईएक्स तथा अन्य आवश्यकताओं की भी आंशिक पूर्ति करेंगे।

3. बीएसएनएल और एमटीएनएल आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के जरिए 50 साल और उससे अधिक आयु के अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की भी पेशकश करेंगे। जिसका वहन भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता से किया जाएगा। वीआरएस के अनुग्रह राशि संघटक के लिए 17,169 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, भारत सरकार पेंशन, ग्रैज्युटी और रूपांतरण की लागत का वहन करेंगी।
4. बीएसएनएल और एमटीएनएल अपनी परिसंपत्तियों का मुद्रिकरण करेंगे, ताकि ऋण चुकाने, बॉन्ड्स की सर्विसिंग, नेटवर्क का उन्नयन, विस्तार एवं परिचालन संबंधी धनराशि की आवश्यकताएं पूरी जा सके।
5. बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी।

आशा है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल में नई जान डालने वाली उक्त योजना के कार्यान्वयन से वे दोनों अपने सुदृढ़ दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों सहित समूचे देश में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकेंगे।

आरकेमीणा/आरएनएम/एम/आरके/डीके-

(रिलीज़ आईडी: 1588894) आगंतुक पटल : 92

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Bengali , English , Urdu , Marathi , Gujarati , Tamil , Malayalam